

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक): देहरादून: दिनांक: 21 जनवरी, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में बेसिक शिक्षा हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1345/म0भो0यो0/2007-08, दिनांक 24.09.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रसोई उपकरण आदि के लिये गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पुनर्वैद्य किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2007-08 में विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने संबंधी योजनान्तर्गत कुल रु0 179392.00 हजार (रुपये सत्रह करोड़ तिरानवें लाख बयानवें हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह स्वीकृति पूर्व में शासनादेश संख्या-548/XXIV(1)/2007-52/2006, दिनांक 14.08.2007 में स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त है:-

(क) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों में

कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) योजनाओं की विभिन्न गतियों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।
- (2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- (3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चातू वित्तीय वर्ष की ज़ेनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न लगायी जाय।
- (4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्याधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।
- (5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें। उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
- (7) अवशेष धनराशि की जिलावार फाँट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जायें, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फाँट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय-01-केंद्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ-0102-विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता-आयोजनागत की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-897(P)/वित्त व्यय नियंत्रक अनुभाग-3/2008, दिनांक 14 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
3. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
4. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. ✓ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

16/1
(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
अपर सचिव।